

जिस देश में मान नहीं, जीविका नहीं, बधु नहीं और
विद्या का लाभ भी नहीं है, वहां नहीं रहना चाहिए
- आचार्य चाणक्य

‘‘पद्मावती’’

मझोले व्यापारी वर्ग के आक्रोश और खासकर, नाक का मुद्दा बनते जा रहे गुजरात चुनाव की वजह से सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है। जीएसटी परिषद की कोशिश 28 प्रतिवर्त बाले सर्वोच्च टैक्स स्टैब में से रोजर्मार्ड में काम अनें बाली कुछ वस्तुओं तथा मुख्य रूप से छोटे एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) द्वारा बनाये जाने वाले तथातों को निमत्त टैक्स में लाने की है। 9-10 नवम्बर को आक्रमण के गुवाहाटी में आयोजित होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होगी। वहां इसके पूरे आसार हैं कि न केवल एसएमई द्वारा टैक्स फ़ाइल करने की योजना (कार्पोरेशन स्कीम) और सरल व उत्तर बनाई जाएगी बल्कि एसएमई वर्ग के उत्पादों के मामले में उन्हें और अधिक राहत भी दी जाएगी। टैक्स निर्धारण समिति, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल हैं, इदिनों अनथक रूप से ऐसी वस्तुओं और उत्पादों की फ़ाइचन करने के काम में जुटी है, जिन पर टैक्स स्टैब को और भी कम किया जा सकता है। सरकार ने अक्टूबर के प्रारंभ में आयोजित जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में भी मुख्य रूप से देश के छोटे व्यापारियों एवं नियांतकों की शिकायतों एवं उन्हें हो रहीं परेशानियों को दूर करते हुए कई अहम कदम उठाए थे और 27 वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी की कदम कर दी गई थी। व्यापारियों का करों की फ़ाइलिंग और भुगतान से जुड़ी राहत दी गई थी और उत्से सर्वोच्च कार्पोरेशन स्कीम की अधिकारी समिति 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई थी। वहां, 1 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर बाले छोटे व्यापारियों को मासिक की जगह त्रैमासिक कर भुगतान तथा रिटर्न फ़ाइल करने की सुविधा दी गई थी। लेकिन वे कदम पर्याप्त नहीं थे। छोटे व्यापारी लगातार शिकायत करते ही रहे हैं कि जीएसटी ने उन पर न केवल करों का बोझ बढ़ा दिया है बल्कि टैक्स फ़ाइल करने की प्रशासनिक प्रक्रिया को भी और दुख़बना दिया है। यही वजह है कि सरकार एवं व्यवस्था में और संस्थान बदलने को मजबूत दिख रही है। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जीएसटी व्यवस्था को समल बनाने के लिए कई सकारातमक घोषणाएं की थीं। अब देखना यह है कि जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में एसएमई क्षेत्र के लिए सरकार के पिटारे से क्या निकलता है?

दागियों की भरमार

वरेर्च्च न्यायालयों ने डीम्ड विविदालयों द्वारा दूस्रस्थ शिक्षा के तकनीकी या विज्ञान के पाद्यक्रमों पर जो रोक लगाई है, उसे देर से आया दुर्स्त फैसला कहना उचित होगा। दूसरथ शिक्षा के माध्यम से तकनीकी और विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्रों को व्याख्याहिक ज्ञान या तो होता ही नहीं है अथवा कम होता है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सापकदिव्या है कि सभी तकनीकी पाद्यक्रम फैसले के दायरे में आएंगे; इसलिए मैटेडिकल, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर विज्ञान और फार्मेसी समेत कई अन्य पाद्यक्रम, जो तकनीकी पाद्यक्रम की श्रेणी में आते हैं, की पढ़ाई अब प्रत्याखार के माध्यम से नहीं कराई जाएगी। जिन छात्रों को इन विविदालयों ने डिग्रियां प्रदान कर दी हैं, उनकी 2001 से 2005 के बीच की सारी सारी डिग्रियों को रद दिया गया है। कुछ लोग हड्ड कसकते हैं कि उनमें सारे छात्र अयोग्य ही होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कारण, कई ऐसे विविदालय कुछ प्रायोगिक कक्षाएं कहीं-कहीं लगावते भी थे। शायद इसी का ध्यान रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। प्रत्येक छात्र को पास करने के दो अवसर मिलेंगे। यहीं उचित तरीका है। जो छात्र इसमें सफल होते हैं, उनकी डिग्री मान्य, जो छात्र होते हैं, उनकी खस्त है। हाँ, जो छात्र परीक्षा नहीं देना चाहते उनकी फौजी की रोशि संबंधित विविदालय को वापस करनी होगी। वास्तव में निजी विविदालयों को सरकार द्वारा बदलाव देने की नीति के कारण वह देखा गया है कि पिछले कछ वर्षों में ऐसे विविदालयों की बढ़ा सी आ गई थी। यह दिखाई दे रहा था कि इनमें शिक्षा और डिग्री को मजाक बना दिया जा परे। इनकी दूठाने कलताने रहीं। यूजीसी और एआईसीटीई के होते हुए कैसे ऐसा हुआ है, यह समझ के परे है। आशिर्य यूजीसी ने एआईसीटीई के नियमों की अनदेखी करते हुए इन डीम्ड विविदालयों को ऐसी डिग्रिया देने के लिए मान्य कैसे कर दिया ? इसलिए सुधीर मार्क ने इसकी जांच की आई से करने का निर्देश दिया है। ऐसी स्थानांतरों का समृद्धि के से नियमन करना भी जरूरी है। इसीलिए न्यायालय ने केन्द्र से तीन सदस्यीय समिति का गठन कर उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए नियमन बनाने को कहा है।

सत्संग

श्रेष्ठ में लगाएं अपनी सारी क्षमता।

समाज में दिनों-दिन बढ़ता व्यभिचार चिंतनीय और सोचनीय है। व्यभिचार मनुष्य के भ्राता हाने की पराकाशा है और यह मनुष्य के पतन की निशानी भी है। व्यभिचार का मुख्य कारण धौतिकवाद है और आज जिस तरह पैसे को हक्क मनुष्य के सिर पर सवार हो गई है, उससे मनुष्य यह मान बैठा है कि पैसे के दोपहर पर जायज़-नाज़ायज़ सब कुछ संभव है। यह अपने पैसे से किसी को भी खरीदा या उत्पाद का शोधन कर सकता है। हम मनुष्य को सबसे बड़ी खल है कि जो पैसा उसके जीवन जीने का एक साधन मात्र था, उसे उनसे अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बना दिया है। जिसका परिणाम यह है कि मनुष्य पैसे का उपभोग करम और पैसा उसका उपयोग ज्यादा कर रहा है। आज समाज में आधुनिकता और आजादी के नाम पर मर्यादा का घोर हनन हो रहा है और चारों ओर व्यभिचार का बोलबाला है। आर्थिकजनक बात यह कि सभ्य कहे जाने वाले समाज में व्यभिचार का प्रत्रय और बढ़वाहा रहा है, तो प्रत्रय और बढ़वाहा की बात करने वालों को शंका की नज़रें से देखा जा रहा है। किसी भी समाज के विकास एवं सूख-शांति का आधार उसकी सभ्यता-संस्कृति होती है, लेकिन जब लाग ही अपने समाज के आधार स्तम्भों को ढहाने लगें, तब समाज का अस्तित्व बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता। जिस तरह भारतीय समाज ने भी अपना संस्कृति-सभ्यता का त्यागकर परिश्रम की भोगवादी संस्कृति को अंगीकार किया, उसी का परिणाम है कि हमारे समाज में व्यभिचार और भ्रष्टाचार जैसे तमाम दुर्फर्म बढ़ गए हैं। हमारा समाज नानता, सद्व्यवहार, शांति, एकता इत्यादि का प्रतीक है, जबकि भोगवाद का मतलब दमन और निरंकुशता है। किसी भी समाज में सूख-शांति बनी रहे, इसके लिए नैतिक और चारित्रिक माहौल का हाना आवश्यक है। केवल कड़े कानून बना देने से बात नहीं बनती। कानून का भय हमें सभ्य नहीं बना सकता, बल्कि सच यह है कि कानून के डर से मनुष्य अपराध करने से पहले सतर्क हो जाता है और अपने चरित्र का निर्माण करके और निर्मितता को अपनारहर ही कोई मनुष्य सभ्य-संस्कृती बन सकता है। ऐसे में, यह जल्दी हो गया है कि आधुनिक विज्ञान को शिक्षा के साथ बच्चों में संस्कृती और उनके चरित्र का निर्माण किया जाए, ताकि अपराध, व्यभिचार, भ्रष्टाचार इत्यादि पर अंकुश लग सके। व्यभिचार का मूल कारण मनुष्य का नजरिया है।

प्रवक्ता हुआ चुनियंग का बयान

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनियांग का बयान है कि हमने प्रस्ताव को तकनीकी तौर पर रोक रखा था ताकि इस मसले पर समिति के सदस्यों को सोचने का और वक्त भिल सके, लेकिन अभी भी इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। जाहिर है, यह तर्क केवल अपने पक्ष को सही ठहाने के लिए दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि एक आतंकवादी के लिए एक अकेला देश अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनने से रोक रहा है, ये जानकर हमें फ़िर निराशा हुई। हमारा मानना है कि दोहरे मापदं आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई को कमज़ोर करेंगे भारत के कथन से दुनिया के बे सारे देश सहमत होंग।

सतीश पेडणोकर



जैसा के बारे में पूरी तरह जन गई है। दुनिया को यह भान हो गया है कि वह एक आतंकवादी है जिसे चीन पाकिस्तान में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बचा रहा है। यही नर्सा सफलता है। यह बात ठीक है कि अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया जाता तो उस पर कई तरह के प्रतिवध लगा जाते एवं पाकिस्तान के लिए उसकी रक्षा करने का कोई आधार नहीं बचता। लेकिन प्रतिवध नर्सा भी लगा तो भारत के प्रयासों से उसकी कुख्याति इतनी हो गई है कि पाकिस्तान खुलकर उसके पक्ष में कभी नहीं आ सकता। वह विदेशी की यात्रा से भी बचेगा। यही नहीं उसके लिए खुलकर पहले की तरह फंड एकत्रित करनी चाही थी कठिन होगा। वास्तव में भारत ने अपने लगातार प्रयास से यह साकृत कर दिया है कि पाकिस्तान चीन के माध्यम से मसूद अजहर जैसे खूबार आतंकवादी को बचा रहा है। पाकिस्तान को लेकर दुनिया में जो धारणा बनी है वह कहा दें शिष्यों नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महान्यौवेशन संभव हो गया है कि एक साथ तीन देशों बांलादेश, अफ़ग़ानिस्तान और उसके नें के, अधिकार के तहत बयान देने वालकविद्यों का घोषित शरणारथी द्वितीय पुष्पित होता है और कई बार चीन आखिर अपने आर्थिक एवं तिर कहाँ-कहाँ और कितना कर

चलते चलते

नदियाँ

नदियों का हमारे जीवन में बेहतर स्थान है। गंगा और अन्य पवित्र नदियों के किनारे ही हमारी सभ्यता और स्कृति फली-फली है। इनका बिना किसीसे भी नहीं किए जाएं। लेकिन क्या एक कल्पना ही नहीं ही जा सकती है? इसके बाद हमारे ऋषि-मुनियों ने नदियों को पाण्डाक विद्युत देना है। यही वजह है कि नदी को मान करता है कि हमसिल है। लेकिन क्या मां पर उसकी विद्युत नम हमर रसमधार्यगी के लिए प्यारी है? तारी है या उक्ता दिखावा करती है? अतिकर्तिक पूर्णिमा पर नदियों के किनारे दीपाली जलना है दुबकी लाना ऐसी आशा की जिस पर आज की पोढ़ी को सोचना चाहिए। यह सवाल इसलिए किया जाएगा कि बप-त्योहार का वक्त आता है तो हम नदियों पर इस कदर प्यार लुटाते हैं जिसके बाब नहीं है। मार माल के बाकी बचें तो हम नदियों अपनी बेदरी पर एक रुहानी हाती हैं। यह भले नदियों के किनारे रहती है।

चीज़ की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हमारे ऋषि-मुनियों ने नदियों को पोषक माना है। यहीं वजह है कि नदियों को मां का दर्जा विसिल है। लेकिन वर्तमान पर उसकी संतान महज रस्मअदायक के लिए प्यार लूटाई है कि यह उसका दिव्य करती है? कार्यकृत पूर्णिमा पर नदियों किंवदि दीप पञ्चलब

हैं किंतु हम अभी भी नदियों के करीब नहीं हो सकते हैं। और जब तक हम पवित्र और ईमानदार तौर परीकों से मां समाज नदियों के साथ नजदीकि-

नहीं बढ़ाएगे, तब तक न सिफर हास्यों नदियों कला
रहेगी वर्त आने वाली पौधी भी हमें माफ़
करेगी। हमारा देश उत्तरप्रिय है। लेकिन हम
अपनी जिम्मेदारियों और सुख-दुख के भाव से पै
छड़ाने वाली सीचे के पिछलगूँ हो गए हैं। कर्मा
पूर्णिमा या ऐसे किसी अन्य त्रिपुराओं आयोग-उत्तर
जनका का थायर, उत्करी निषा, उत्करी आयोग-उत्तर

मुद्दा

“अतिथि देवो भवः”

की तस्वीर उतारने और बीड़ियों बनाने में मशहूर थे। बहाहाल, दोनों सैलानियों को दिल्ली के अस्पताल में पर्चट की कराया गया। बताते हैं कि अभी भी सुनने परेशानी हो रही है। बिंदंबाना है कि यह सब हुआ जब भारत सरकार पूरे देश में पर्टन को बदल देने के लिए पर्टन पर्व का आयोजन कर रही थी। घटना का चिंताजनक प्रभाव यह है कि स्थानीय पुलिस ने राजनीति के पुलिस मुख्यालय की भी इस घटना वाले में अन्योनीम रेखा और समय से सच्चाना तक देखा है। अन्योनीम पुलिस की गवाही मिलादारी है इस पुलिस मुख्यालय को अवगत कराए। इस घटना का जानकारी भी तब आम हुई, जब अगले दिन पर्व का समापन समारोह मनाया जा रहा था। बिंदंबाने मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मामले का संज्ञन लिया और प्रधान सरकार से इस बारे में रिपोर्ट तलब है। एआई दिन ऐसी वारदात मिलादारी की बनती हैं—कभी अजमेर-पुँजक से तो कभी गयां कभी बनारस से तो कभी इलाहाबाद, हरिद्वार, मथुरा, वृदावन, खुगाहान, गोवा आदि स्थानों से इस की खबरें आती रहती हैं। पिछले साल पर्वकर्त्ता नीदरलैण्ड की एक युवती के साथ मध्यप्रदेश में दुर्घटना किया गया, जिसमें होमार्ड के दो जवानों द्वारा प्रतिपात्र की किया गया था। इसी तरह, जानपरी 2016 में बिहार के गया जिले में एक युवती बलत्कार किया गया था। अभी इसी साल अप्रैल राजस्थान के अजमेर घूमने आए एक स्पेनिश र

जिजीविया तो चरम पर होती है मगर उसके अगले ही दिन सारी अच्छी भावनाएं विलीन हो जाती हैं। ऐसे में नदियों का पुनरुज्जीवन या उसके स्वच्छ रहने की परिकल्पना कैसे मूर्त रूप से सकती है? नदियों से रिसाव कैसे सुधारा जाए, इस पर मंथन की जरूरत है।

नदियों को परिष्कृत करने के दावे कैसे सिफर एक दिन के घ्यार उड़लेन से नदियों के प्रति हमरी स्थायी भले किसी तरह सिसकती हुई बढ़ती रहे। परंतु इसमे बेहतरीनी की आस रखना खुद की धीखा देना चाहिए है। पूर्व की हायारी गलतियों का ही नतीजा है कि न केवल नदियां सुख रही हैं बल्कि गंदे नालों में तब्दील होती जा रही हैं। मगर इसकी वजह हम ही हैं। जब तक हम अपनी दकियानसी सोच को नहीं दफना देते, तब तक नदियों को बेहतरी के बारे में सोचना भी अपराध है।

संवैधानिक आधार पर नजर

आभा स्वामी
 योजना से बैंक खालों, मोबाइल कनेक्शन और
 जनाओं के लाभों को जोड़ने की कंटेंड सरकार
 नेक है यह सबका ये सवाल अभी सोचकरो
 तो एक चीज पश्चिम बंगाल सरकार भी इस योजना
 लेकर अद्वितीय पहुँच गई। इससे अजीब
 तो सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये
 दाय कि संसद स पारित किसी कानून को कोई
 बुलोती दे सकती है? स्पष्टतः पश्चिम बंगाल
 चे की मयादाओं का खाली नहीं किया।
 तो स्पष्ट करना पड़ा कि कंटेंड की किसी को
 उसे लागू करने की वजह नहीं।

पहले चुनावों में सफेद काइ नामांकित हो द सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जोगी ने कहा- 'ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से याचिका दें, तो हम उस पर सुनवाएँ करेंगे। जहां तक 'आधार योजना पर उठे सर्वेधानिक सवालों की बात है, तो वो पहले ही कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच चुके हैं। इनका शीघ्र समाधान हो, यह न सिर्फ याचिकाकर्ता, बल्कि सरकार भी याहांती है। एटॉनी जनरल कंपनी

वेणुगोपाल ने सीमावार को सूप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार अपना पाप सख्ती की तैयार है। अगर ज्यायालय को आवश्यक लगे, तो वह सरिधान पीट बना सकता है। संतोष की बात है कि कोर्ट ने तुरंत इस सुनाव पर कदम उठाया। प्रधान ज्यायाधीश जर्सिट्स दीपक मिश्रा ने आधार योजना से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय सरिधान पीट बनाने की घोषणा की। ये बेंच नवंबर के आसीनी हज़ेर से सुनवाई शुरू कर देगी। अब अपेक्षित है कि सर्वजनिक घर्षणों में आधार योजना से

संबंधित घरांओं और अप्राप्यता पर तुरंत विदम लगे।

एटनी जनरल ने जिक्र किया कि इस संविधं में कई झूठी बातें फैलाई गई हैं। मासलन, यह निराधार भय फैलाया गया है कि सीधीएसड धोरकाओं में भाग लेने के लिए छात्रों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। ऐसी बातों से अच्छे उद्देश्य से लागू की जा रही इस महत्वपूर्ण योजना को लोकर लोगों में बेवजह अंदेशे पैदा होते हैं। जबकि आवश्यकता लोगों में वह भरोसा पैदा करने की है कि आधार कार्ड उनके और देश के भले के लिए है। इसके जरिए किसी से कोई जार-जबरदस्ती नहीं है। अब सबके लिए उचित वह होगा कि वे संविधान पीठ के निर्णय का इंतजार करें। सरकार विभिन्न सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है, लेकिन कोर्ट का फैसला आंतरिक तक इसे किसी क्षेत्र में अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। कुछ याचिकाओं में दलाल दी गई है कि आधार योजना नागरिकों की निजात में दखल है। पिछले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने निजत का नापारिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया था। उसके बाहर कुछ हलकों से जल्दी दूर गई कि अब आधार योजना की वैधानिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। इन सारी बातों से ऊहापोक बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि यह ग्रम जल्द ही छंट जाएगा और आधार कार्ड के संवैधानिक एवं वैधानिक आधार पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

